other meat and meat processing facilities, tuna and other fish processing, setting up of cold chain, Research and development in food processing and packaging and training of manpower in certain sector; Assistance under these schemes can be availed by organisations/institutions in Bihar. Some assistance have already been availed by organisations in Bihar for setting up of Food Processing Training Centres for training of rural youth with a view to setting up of small food processing units.

Disposal of letters received from M.Ps

2307. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministy during the period from 1st April, 1990 to 31st March, 1993 alongwith year-wise details thereof;

(b) what is the number of letters out of them that were acknowledged;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) 1990-91 — 26

1991-92 — 19

1992-93 — 57

Total — 102

(b) 97

(c) 93

(d) Positive replies were sent in 74 cases and negative replies in 19 cases.

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश

2308. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का आंकलन करने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र मे निवेश की संभावनाओं का आकलन करने हेतु क्या विशिष्ट प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है । मंत्रालय की योजना स्कीम में राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन करने और आगे विकास करने के लिए सहायता देने की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी किसी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है ।

तथापि जुलाई 1991 में उदारीकरण किए जाने के बाद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है । अगस्त 1991 से जनवरी 1994 तक, उत्तर प्रदेश के लिए 515 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें 7,550 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जाएगा, प्रस्तुत किए गए हैं प्रस्तावित पूंजी निवेश और रोजगार का उल्लेख करते हुए जनवरी, 1994 तक प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का राज्यवार सारांश विवरण में दिया गया है ।